



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 477 ]  
No. 477]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 1997/अग्रहायण 11, 1919  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 1997/AGRAHAYANA 11, 1919

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 683( अ ).—केन्द्रीय सरकार, दूर संचार विनियामक अधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1997 का 24 ) को धारा 35 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ) नियम, 1997 है।

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. ( क ) अध्यक्ष प्रति मास 9,000/-रु. ( पूर्ण पुनरीक्षित ) बेतन प्राप्त करेगा, और

( ख ) सदस्य प्रतिमास 8,000/-रु. ( पूर्ण पुनरीक्षित ) बेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त फायदों या अन्य रूपों में सेवानिवृत्त फायदों को प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त किए हैं या जो प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है, जैसे मध्यम या सदस्य का बेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली भेंशन या अभिदायी भविष्यि निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्त फायदों ( उपदान के समतुल्य भेंशन को छोड़कर ), यदि कोई हो, की सकल रकम को घटा दिया जायगा।

### 3. महंगाई भत्ता

अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य बेतन लेने वाले समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

परन्तु यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह केन्द्रीय सरकार के समतुल्य बेतन लेने वाले समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा, किन्तु ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद धारण करने की अवधि के दौरान भेंशन के संबंध में महंगाई राहत का संदाय निलंबित रहेगा।

[फा. सं. 1-1- 94-टी सी ओ ( जिल्ड-IX )]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1997

**G. S. R. 684 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 8-9-1995.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7 after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:—

**“EXPLANATORY MEMORANDUM**—It is clarified that the provisions of sub-rule (2) does not adversely affect any of the employees of the Finance Commission of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands by its retrospective effect.

[F. No. U-11022/1/94-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number GSR 28(E) dated 12-1-96, GSR 228(E) dated 28-5-96 and GSR 307(E) dated 5-6-97.